राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापुर , गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, मंगलवार, 06 जनवरी 2026
वर्ष 14, अंक 263, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

पीआरवी पर पथराव मामला 5 आरोपी गिरफ्तार, दो पक्षों के विवाद में दो दिन पहले हुई थी घटना..03

पट्टे की जमीन किसी की आवास योजना किसी का बकहो नगर परिषद में खेल..04

उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताई वजह?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य पांच आरोपियों गुलफिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी. अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत तय वैधानिक कसौटी को पूरा करता है. इसी आधार पर कोर्ट ने माना कि इस चरण पर उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि लंबे समय तक हिरासत में रहना अपने आप में जमानत का आधार नहीं बन सकता. कोर्ट ने कहा कि देरी को 'ट्रंप कार्ड' की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खासकर जब मामला यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत दर्ज हो. अदालत के अनुसार, हर आरोपी की भूमिका का अलग-अलग मूल्यांकन करना आवश्यक है और सभी आरोपियों को एक ही तराजू में तौलना न्यायसंगत नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी भी की कि कुछ आरोपियों की 'केंद्रीय भूमिका' होती है, जबकि कुछ की भूमिका केवल सहायक या मददगार की होती है. इन दोनों के बीच फर्क किए बिना फैसला करना अपने आप में मनमाना होगा. कोर्ट ने माना कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग और अधिक गंभीर प्रकृति की प्रतीत होती है।

अदालत ने यूएपीए की धारा 43डी(5) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान जमानत के सामान्य नियमों से अलग है. हालांकि यह न्यायिक जांच को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन अदालत को यह देखने की जरूरत होती है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं. कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि 'आतंकी कृत्य' केवल प्रत्यक्ष हिंसा या जान-माल के नुकसान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आवश्यक सेवाओं में व्यवधान डालना और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करना भी इसके दायरे में आता है. इसी कसौटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर उपलब्ध अभियोजन सामग्री से उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होते हैं और यूएपीए के तहत तय वैधानिक सीमा उन पर लागू होती है. इसलिए मौजूदा चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता।

वहीं, कोर्ट ने गुलफिशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत देने की अनुमति दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि इन पांच आरोपियों को जमानत देने का मतलब उनके खिलाफ आरोपों में कोई ढील नहीं है. उन्हें सख्त शर्तों के साथ जमानत दी गई है और यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का पूरा अधिकार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई लगातार चलनी चाहिए, ताकि ट्रायल में अनावश्यक देरी न हो. अंत में अदालत ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों और उनकी टीम द्वारा दी गई सहायता की सराहना भी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में हैं, लेकिन देरी को ट्रंप कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा, 'सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना ज़रूरी है. यूएपीए की धारा 43डी(5) जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है. यह न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता है या डिफ़ॉल्ट होने पर जमानत से इनकार को अनिवार्य नहीं बनाता है. लोगों को मारने या विनाश के अलावा, यह प्रावधान उन कृत्यों को भी शामिल करता है जो सेवाओं को बाधित करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा, 'जमानत बचाव पक्ष के मूल्यांकन का मंच नहीं है. न्यायिक संयम कर्तव्य का परित्याग नहीं है. सही प्रयोग के लिए न्यायालय को एक व्यवस्थित जांच करनी होगी.' सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सवाल किया, 'क्या जांच से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होते हैं? क्या आरोपी की भूमिका का अपराध करने से कोई उचित संबंध है?' कोर्ट ने कहा, 'आतंकी कृत्य केवल हिंसा तक सीमित नहीं, बल्कि आवश्यक सेवाओं में व्यवधान भी इसके दायरे में आता है. सभी आरोपी एक जैसे नहीं हैं. उमर खालिद और शरजिल इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है।'

बंगाल चुनावः भाजपा नेता ने बैठे-बैठाए टीएमसी को थमा दिया मुद्दा, अब डैमेज कंट्रोल करने में जुटी पार्टी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल में भाजपा डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है. पार्टी के एक केंद्रीय नेता की अवैध बांग्लादेशियों और मतदाता सूची में नाम शामिल करने संबंधी टिप्पणी से मामला बिगड़ा है. भाजपा की राज्य इकाई परेशान है. दरअसल, भाजपा नेता की इस टिप्पणी ने मतुआ बहुल इलाकों में तृणमूल कांग्रेस को नया हथियार दे दिया. दरअसल, विवाद की शुरुआत तब हुई जब भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कोलकाता में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए।

क्या था बयान

उन्होंने कहा कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से आया है, उसका नाम जाति-धर्म से ऊपर उठकर वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए. यह बयान ऐसे समय में आया है जब शरणार्थी बहुल क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर पहले से ही चिंता का माहौल है. मतुआ समुदाय के एक बड़े वर्ग को आशंका है कि चुनाव से पहले उनके नाम सूची से हटाए जा सकते हैं. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने तुरंत पार्टी को आर्य के बयान से अलग कर लिया और इसे उनका व्यक्तिगत राय बताया।

पार्टी ने खुद के बयान से अलग किया

उन्होंने कहा कि हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते. यह भाजपा की आधिकारिक नीति नहीं है और पूरी तरह इसके विपरीत है. हम उनकी इस टिप्पणी का समर्थन नहीं करते. भट्टाचार्य ने आगे कहा कि ऐसे मेहमान बंगाल भाजपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए स्वागत योग्य नहीं हैं. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि ऐसे नेताओं को बंगाल भेजकर मीडिया से संबोधित नहीं कराया जाए. एक असामान्य कदम में बंगाल भाजपा ने आर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लिंक अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया है. ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्य ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य के कुछ नेताओं के साथ मिलकर की थी. आर्य का बयान बंगाल में भाजपा की व्यापक राजनीतिक रणनीति से पूरी तरह उलट है. पार्टी बार-बार आश्वासन देती रही है कि कोई भी मतुआ सूची से बाहर नहीं रहेगा और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत सभी पात्र शरणार्थी नागरिकता प्राप्त कर मतदाता सूची में अपना स्थान वापस पा लेंगे. एक पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मतुआ और नामशूद्र समुदायों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हालिया कोलकाता यात्रा के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था कि शरणार्थियों में किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए. इसी कारण आर्य की टिप्पणी को नीति नहीं, बल्कि अपवाद माना जा रहा है. उन्होंने निजी तौर पर स्वीकार किया कि इस बयान से संवेदनशील राजनीतिक समय में अनावश्यक भ्रम पैदा हो गया है।

भाजपा हुई असहज

पार्टी के अंदर भी असहजता साफ दिखी. भाजपा नेता सजल घोष ने खुलकर आर्य से असहमति जताई और कहा कि बांग्लादेश से आए सभी लोगों को स्वतः अवैध नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश से आए हर व्यक्ति को अवैध नहीं कहते. हिंदू शरणार्थी शरणार्थी हैं, घुसपैठिए नहीं. सरकार की घोषित नीति है कि पात्र गैर-मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी।

तृणमूल ने मौके को लपक लिया

तृणमूल कांग्रेस ने इस मौके को तुरंत लपक लिया. पार्टी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि क्या राज्य के भाजपा नेता केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं. ये भाजपा का असली चेहरा है. इनका निशाना बंगाली हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मतुआ समुदाय का होगा. उन्होंने संकेत दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी मतुआ बहुल क्षेत्रों में इस बयान को बड़े पैमाने पर प्रचारित करेगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना बंगाल भाजपा को मुश्किल स्थिति में डाल सकती है।

कोलकाता के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि आर्य का बयान पार्टी के शरणार्थी समुदायों तक पहुंच बनाने की रणनीति के खिलाफ है. वीडियो को जल्दबाजी में हटाना पार्टी की शर्मिंदगी की गहराई दिखाता है. मतदाता सूची संशोधन पहले से ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है. भाजपा नेताओं को आशंका है कि तृणमूल कांग्रेस इस विवाद को हथियार बनाकर मतुआ मतदाताओं में असुरक्षा की भावना भड़काएगी. दक्षिण बंगाल में मतुआ वोट भाजपा की चुनावी गणित के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

संक्षिप्त ख़बरें

खेतलपुर हादसे के पीड़ित परिवार से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, प्रशासन से सहायता की मांग की

भदोही। औराई विकास खण्ड के विसापुर न्याय पंचायत अंतर्गत ग्राम सभा खेतलपुर में 12 दिसंबर को ट्रैक्टर की चपेट में आकर हुई सुजीत कुमार पटेल की दर्दनाक मृत्यु के मामले में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडेय एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाए जाने की मांग की। इसके उपरांत उप जिलाधिकारी, औराई को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे में शासन-प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में ब्लॉक अध्यक्ष शिवपूजन मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष दीनानाथ दुबे, जिला महासचिव अवधेश कुमार पाठक, संजय जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार पटेल सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी।

विकास भवन के पशुधन कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग, अहम दस्तावेज खाक; बाल-बाल बचे कर्मचारी

बलिया। विकास भवन स्थित पशुधन विभाग कार्यालय में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में विभाग की कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर नष्ट हो गईं, जबकि समय रहते बाहर निकल जाने से सभी कर्मचारी सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब दो बजे कार्यालय के एक हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने कागजातों को अपनी चपेट में ले लिया। धुआं फैलने से कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद सभी लोग कार्यालय छोड़कर बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई, जिससे आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पशुपालन विभाग के कनिष्ठ सहायक कुमार अमृत राज ने बताया कि विद्युत तारों में स्पार्किंग होने से आग लगी, जिसमें कुछ आवश्यक दस्तावेज जल गए, हालांकि कर्मचारियों की तत्परता से कई फाइलें सुरक्षित भी बचा ली गईं।

मेरी बात नहीं मानी तो मादुरो से भी बुरा हाल करूंगा, ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को धमकाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

वेनेजुएला में अमेरिका के घुसकर राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. निकोलस मादुरो जहां अमेरिका की जेल में हैं तो वहीं अब ट्रंप ने नई धमकी दी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने अमेरिका के साथ सहयोग नहीं किया तो उन्हें अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. यानी उनका हाल उनसे भी बुरा होगा. 'द अटलांटिक' पत्रिका को फोन पर दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर रोड्रिगेज 'सही काम' नहीं करतीं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है.

ट्रंप की बात नहीं सुनी तो क्या होगा?

हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस कीमत का मतलब क्या होगा, लेकिन संकेत साफ हैं कि इसमें गिरफ्तारी, सत्ता से हटाना या कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है. यह बयान ऐसे समय आया है जब शनिवार तड़के अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला में एक हाई-प्रोफाइल सैन्य अभियान चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से गिरफ्तार किया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाकर 'नार्को-आतंकवाद' और अवैध हथियारों से जुड़े मामलों में जेल भेज दिया।

हालांकि ट्रंप की सख्त भाषा के उलट, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कुछ नरम रुख दिखाया. रुबियो ने कहा कि उनकी डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत हुई है और उन्होंने अमेरिका के साथ सहयोग का संकेत दिया है. रुबियो ने कहा कि रोड्रिगेज के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं और अमेरिका अपनी शर्तों पर बदलाव चाहता है।

वेनेजुएला मामले पर क्या है दुनिया का रिएक्शन?

इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है. ट्रंप जहां बार-बार कह चुके हैं कि अमेरिका वेनेजुएला को 'स्थिरता आने तक' चलाएगा और उसके विशाल तेल संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, वहीं विशेषज्ञों को डर है कि यह अमेरिका को एक और लंबे विदेशी हस्तक्षेप में फंसा सकता है, जैसा इराक और अफगानिस्तान में हुआ था. हमले के कुछ ही घंटों बाद चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका की कार्रवाई को एक संप्रभु देश के खिलाफ 'घमंडी ताकत का इस्तेमाल' बताया और कहा कि इससे लैटिन अमेरिका की शांति खतरे में पड़ सकती है. ब्राजील, मेक्सिको, चिली, स्पेन और उरुग्वे समेत कई देशों ने भी इसे खतरनाक मिसाल करार दिया।

आगे किन देशों पर बढ़ सकता है दबाव?

वेनेजुएला के भीतर हालात तनावपूर्ण हैं. रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाड्रिनो ने कहा कि देश की सेना को संप्रभुता की रक्षा के लिए सक्रिय कर दिया गया है और उन्होंने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर समर्थन दिया है. वहीं मादुरो के समर्थक और उनके बेटे ने लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की है. इस बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह वेनेजुएला की सरकार के बचे-खुचे ढांचे के साथ तभी काम करेगा जब अमेरिकी निवेश, खासकर तेल क्षेत्र में, को पूरी छूट दी जाए. ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको पर भी दबाव बढ़ सकता है.

संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार को इस पूरे मामले पर आपात बैठक करने वाली है. दुनिया की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि यह संकट सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित रहेगा या अमेरिका की यह कार्रवाई वैश्विक स्तर पर एक बड़े टकराव की वजह बनेगी।

बांग्लादेश चुनाव से पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्टः नेपाल सीमा से भारत में घुसपैठ की कोशिश, बिहार-बंगाल और पूर्वोत्तर पर नजर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में होने वाले चुनावों से पहले भारत में अवैध घुसपैठ की कोशिशें तेज हो रही हैं, और इसके लिए अब नेपाल सीमा को नया रास्ता बनाया जा रहा है। वर्ष 2025 में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बांग्लादेशी नागरिकों को नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करते हुए सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक यह एक नया ट्रेंड है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कड़ी निगरानी के कारण तस्कर (टाउट्स) अब नेपाल मार्ग का सहारा ले रहे हैं। ये तस्कर बांग्लादेश में मौजूद नेटवर्क और भारत में सक्रिय उनके सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में फैली हिंसा ने भारतीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम की गईं। इन्हीं नाकामियों के बाद तस्करों ने नेपाल सीमा को वैकल्पिक रास्ते के रूप में चुना।खुफिया एजेंसियों के अनुसार, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल क्षेत्र से सटी नेपाल सीमा का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जा रहा है। फिलहाल संख्या कम है, क्योंकि तस्कर 'हालात को परख' रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने चेताया है कि रास्ता सफल होते ही बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं।

इसके अलावा, बहराइच, गोंडा और बलरामपुर जिलों के रास्ते भी अवैध घुसपैठ के प्रयास किए गए हैं। हालात को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने नेपाल सीमा पर 1,700 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की है और नेपाल से सटे जंगलों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में कुल 9,000 जवान तैनात किए गए हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी ने कहा कि नेपाल सीमा गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। हमें जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में शरण लिए हुए हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि घुसपैठ का उद्देश्य केवल अवैध बसावट नहीं, बल्कि जनसांख्यिकीय बदलाव और आतंकी मॉड्यूल तैयार करना भी है। खुफिया एजेंसियों ने चेताया है कि आईएसआई बांग्लादेश में आतंकी ढांचे को दोबारा सक्रिय कर रहा है, और नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकियों को भेजने की कोशिश हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आईएसआई ने अपनी रणनीति बदली है। नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर सख्त सुरक्षा के कारण अब नेपाल सीमा को कमजोर कड़ी मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले चुनाव और उससे पहले संभावित हिंसा हालात को और जटिल बना सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले चुनावों को देखते हुए भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ महीने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होंगे।

सिख मर्यादा के अपमान का मामला...अकाल तख्त ने पंजाब CM भगवंत मान को किया तलब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब करने का फैसला सुनाया है. 15 जनवरी को उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पेश होना होगा. अकाल तख्त द्वारा भगवंत मान पर कई आरोप लगाए गए हैं. पिछले कुछ दिनों में सिख मर्यादा पर हमला, गोलक और दसवंध पर दिए गए अपमानजक बयान को लेकर उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है. इस पूरे मामले में जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर सिख मर्यादा और अकाल तख्त की सर्वोच्चता को चुनौती दी है. मुख्यमंत्री द्वारा गुरुद्वारों की 'गोलक' (दान पात्र) और 'दसवंध' (आय का दसवां हिस्सा दान करना) के पवित्र सिद्धांतों के खिलाफ की गई अपमानजनक बयानबाजी को सिख भावनाओं पर हमला करार दिया गया है।

गोलक-दसवंध पर अपमानजनक बयानबाजी के आरोप

दरअसल, सीएम मान का एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि इस वीडियो में वह कथित तौर पर सिख गुरुओं और शहीद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तस्वीरों के प्रति अपमानजनक गतिविधि करते दिख रहे हैं. जत्थेदार के मुताबिक, सचिवालय के पास इस घटना की वीडियो क्लिप मौजूद है. भगवंत मान सिख की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें अकाल तख्त की 'फसील' (रोस्ट्रम) के सामने पेश होने के बजाय सचिवालय में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है. बता दें कि यह विवाद तब और गहरा गया जब मुख्यमंत्री ने हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) पर 328 लापता स्वरूपों के मामले को लेकर तीखे हमले किए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि SGPC और अकाली दल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अकाल तख्त को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

116000 पेड़ों का क्या हुआ?... अरावली को लेकर SC का DDA से सवाल, CJI ने मांगी एक्शन रिपोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अरावली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा संस्थान (CAPFIMS) के लिए सड़क निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. DDA ने 473 पेड़ काटने की अनुमति मांगी है. DDA की अर्जी पर सोमवार (5 जनवरी) को सुनवाई हुई. इस दौरान स्ट ने फिलहाल पेड़ों को काटने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.

DDA की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत ने DDA से पूछा कि उन 116000 पेड़ों का क्या हुआ जिन्हें लगाने का दावा किया गया था. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक पिछले निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट नहीं मिलती पेड़ों को काटने की नई अनुमति नहीं दी जाएगी।

'116000 पेड़ों का क्या हुआ?'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होने देंगे. CJI सूर्यकांत ने कहा कि जब तक हमें यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि हमारे निर्देशों का पालन किया गया है हम कुछ भी होने नहीं देंगे. CJI ने DDA से सवाल किया कि 116000 पेड़ों का क्या हुआ?. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चारदीवारी का निर्माण हो चुका है और 28 फरवरी तक पूरा हो जाएगा. इस पर CJI ने कहा कि हमें अनुपालन दिखाइए.

'पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती'

CJI ने कहा कि आप एक दिन में एक लाख से अधिक पेड़ नहीं लगा सकते, इसके लिए जमीनी कार्रवाई दिखानी होगी. पहले आपको खुदाई करनी होगी. उन्होंने कहा कि हमें अब तक मौके पर हुई पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल की जरूरत अहम है लेकिन पर्यावरण की अनदेखी नहीं की जा सकती।

19 जनवरी को अगली सुनवाई

बेंच में मौजूद जस्टिस संदीप मेहता ने भी सड़क चौड़ीकरण और अस्पताल की ओपीडी सुविधाओं पर चर्चा की. कोर्ट ने DDA से मौके पर हुई अब तक की पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. CJI ने कहा कि अस्पताल की आवश्यकता को हमारे पिछले फैसले में मान्यता दी गई है. लेकिन ये लगभग 160000 पेड़ हैं और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ों की काटने की दर शून्य हो और काम पूरा हो जाए. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की गई है, तब तक पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक रहेगी।

नया युद्ध बिना घोषणा- वेनेजुएला और बदलती विश्व व्यवस्था

[दुनिया का नया तख्ता- तेल, सत्ता और रणनीति]

[वेनेजुएला प्रकरण- महाशक्तियों की नस पर चढ़ता तेल]

3 जनवरी 2026 की सुबह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वॉशिंगटन से आई एक घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को झकझोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया कि अमेरिकी सेनाओं ने व्यापक सैन्य कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है जहाँ नार्को-टेररिज्म के आरोपों पर ट्रायल होगा। ट्रम्प ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि वेनेजुएला का शासन और संक्रमण प्रक्रिया अब अमेरिका के "नियंत्रण" में होगी। यह कदम मात्र सैन्य हस्तक्षेप नहीं, बल्कि ऐसा भू-राजनीतिक विस्फोट है जो तेल कीमतों को हिला सकता है और वैश्विक संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करेगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में अमेरिकी प्रभाव की यह सीधी स्थापना रूस, चीन और ईरान के लिए खुला संकेत है। यह संकट केवल ऊर्जा बाजारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को भी चुनौती देगा, जहाँ पेट्रोडॉलर की शक्ति और ब्रिक्स की आकांक्षाएँ आमने-सामने खड़ी हैं।

वेनेजुएला का संकट अचानक नहीं, बल्कि वर्षों की विफल नीतियों का परिणाम है। इसकी नींव ह्यूगो शावेज के दौर में पड़ी, जब तेल आधारित समाजवादी मॉडल को समृद्धि का आधार बनाया गया। समय के साथ भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और आर्थिक कुप्रबंधन ने इस व्यवस्था को खोखला कर दिया। 2014 में वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट ने संकट को उजागर किया और देश अतिमुद्रास्फीति, खाद्य कमी व स्वास्थ्य आपदा में डूब गया। परिणामस्वरूप लाखों नागरिकों का पलायन करना पड़ा। सत्ता बचाने के लिए निकोलस मादुरो ने रूस, चीन और क्यूबा का सहारा लिया तथा अमेरिकी प्रतिबंधों को चुनौती दी। इसके जवाब में ट्रम्प प्रशासन ने दबाव बढ़ाया। सितंबर 2025 से कैरिबियन क्षेत्र में तस्करी से जुड़े जहाजों पर हमलों ने तनाव तेज कर दिया। अंततः डेल्टा फोर्स और सीआईए के संयुक्त अभियान में मादुरो गिरफ्तार हुए। ट्रम्प ने इसे ÷नार्को-आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई÷ बताते हुए वेनेजुएला को "सुरक्षित संक्रमण" तक ले जाने की बात कही। लेकिन आलोचकों के अनुसार वास्तविक लक्ष्य विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण है, जो लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व की वापसी और क्षेत्रीय अस्थिरता का संकेत देता है।

इस संकट का सबसे तात्कालिक प्रभाव वैश्विक तेल बाजार पर पड़ा है। वेनेजुएला फिलहाल वैश्विक आपूर्ति का लगभग एक प्रतिशत, यानी करीब दस लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करता है, लेकिन उसके भंडार दुनिया में सबसे बड़े हैं। हमले के बाद ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें साठ से इकसठ डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहीं, पर भू-राजनीतिक जोखिम के कारण पाँच से दस डॉलर की बढ़ोतरी की आशंका है। यदि उत्पादन या निर्यात बाधित हुआ—जैसे बंदरगाहों की नाकेबंदी या बीमा अड़चनें—तो भारी कच्चे तेल की कमी से डीजल और परिष्कृत ईंधन महंगे हो सकते हैं। अभी बाजार में आपूर्ति की अधिकता है; अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार लगभग अड़तीस लाख बैरल प्रतिदिन का सरप्लस मौजूद है, इसलिए तत्काल असर सीमित रहा। लेकिन संघर्ष लंबा चला तो तेल अस्सी से सौ डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति तेज होगी। विशेषज्ञ इसे अल्पकालिक झटका और दीर्घकालिक संतुलन परिवर्तन मानते हैं।

दीर्घकाल में यह संकट तेल कीमतों पर दबाव भी बना सकता है। यदि अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं और शेवरॉन जैसी कंपनियां निवेश करती हैं, तो वेनेजुएला का उत्पादन दो से तीन मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच सकता है। इससे भारी कच्चे तेल की अधिकता होगी और कीमतें पचास से साठ डॉलर के दायरे में सिमट सकती हैं। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल उद्योग को अत्यधिक लाभकारी बनाएंगी, जिससे पेट्रोडॉलर की पकड़ मजबूत होगी। लेकिन यदि गुरिल्ला प्रतिरोध, आंतरिक विद्रोह या रूस-चीन का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुआ, तो उत्पादन में दस लाख बैरल की गिरावट कीमतों को तीस से चालीस डॉलर तक उछाल सकती है। इससे रूस और ईरान जैसी तेल-निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को गहरा झटका लगेगा। साथ ही यह ब्रिक्स की डी-डॉलराइजेशन रणनीति को कमजोर कर सकता है, जबकि क्षेत्रीय अस्थिरता शिपिंग लागत बढ़ाकर नई चुनौतियाँ खड़ी करेगी।

वेनेजुएला संकट ने वैश्विक कूटनीति में तनाव की नई सीमाएँ खींच दी हैं। रूस और चीन इसे प्रत्यक्ष अमेरिकी हस्तक्षेप मानते हैं। रूस पहले ही सैन्य सहायता दे चुका है, जबकि चीन वेनेजुएला के लगभग अस्सी प्रतिशत तेल निर्यात का आयात करता है। यदि अमेरिका पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है, तो रूस की यूक्रेन युद्ध फंडिंग पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, वहीं ईरान को भी भारी कच्चे तेल के बाजार में नुकसान झेलना पड़ेगा। कुछ विश्लेषक इसे "रिवर्स क्यूबन मिसाइल क्राइसिस" बता रहे हैं, जहाँ रूस या चीन लैटिन अमेरिका में सैन्य ठिकाने बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कोलंबिया, ब्राजील और निकारागुआ जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना के विरुद्ध माना जा रहा है, जिससे वैश्विक कूटनीति कमजोर हो सकती है। इसके बावजूद ट्रम्प प्रशासन इसे "नार्को-टेररिज्म विरोधी कार्रवाई" बताकर वैध ठहराने का प्रयास कर रहा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव गहरा और बहुपक्षीय होगा। तेल कीमतों में उछाल से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जिसका सीधा असर भारत और चीन जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ेगा। भारी कच्चे तेल के बड़े आयातक भारत को विशेष लागत दबाव झेलना पड़ सकता है। इसके विपरीत, कीमतों में गिरावट अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है और शेयर बाजारों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। सुरक्षा दृष्टि से अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, लेकिन लैटिन अमेरिका में विरोध और असंतोष भी तेज होगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पेट्रोडॉलर को अस्थायी संबल मिलेगा, जबकि ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की ओर और तेजी से बढ़ेंगे। यदि संघर्ष पनामा नहर तक पहुँचा, तो वैश्विक व्यापार को गहरा झटका लगेगा।

आगे यह संकट कई राहें अपना सकता है। यदि अमेरिकी संक्रमण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संभाल लेता है, तो तेल उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें संतुलित रहेंगी और रूस-चीन की रणनीतिक स्थिति कमजोर पड़ेगी। किंतु यदि व्यापक प्रतिरोध उभरा, तो यह इराक या अफगानिस्तान जैसा लंबा और महंगा फंदा बन सकता है। गुरिल्ला संघर्ष, आंतरिक विरोध और अंतरराष्ट्रीय दबाव अमेरिकी संसाधनों पर भारी बोझ डालेंगे। कम संभावना लेकिन उच्च प्रभाव वाले परिदृश्य—जैसे लैटिन अमेरिका में रूसी सैन्य अड्डा—दुनिया को नए शीत युद्ध के द्वार पर ला सकते हैं। ऐसे में भारत जैसे देशों को सतर्क नीति अपनानी होगी, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है।

वेनेजुएला का संकट किसी एक राष्ट्र की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोरने वाला तूफान है। तेल बाजारों में यह अस्थिरता के साथ दीर्घकालिक पुनर्संरचना लाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका, रूस और चीन के बीच टकराव और तीखा होगा। यह संकट पेट्रोडॉलर को बल दे सकता है, पर डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को भी तेज करेगा। इतिहास संभवतः इसे ÷ट्रम्प कोरोलरी÷ के रूप में याद रखे—अमेरिकी प्रभुत्व की निर्णायक वापसी। प्रश्न यही है कि क्या यह स्थिरता लाएगा या नए वैश्विक संघर्ष की नींव रखेगा। उत्तर भविष्य में छिपा है, लेकिन दुनिया को इसके लिए तैयार रहना होगा।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

संपादकीय

तेल की राजनीति और सत्ता का खेलवेनेजुएला, अमरीका और 'अमेरिका फर्स्ट' की असहज सच्चाई

वेनेजुएला को लेकर एक बार फिर दुनिया की भू-राजनीति उबाल पर है। जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, वही देश आज राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और अंतरराष्ट्रीय दबावों के चक्रव्यूह में फंसा है। अमरीका द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने, तेल उद्योग में सीधे दखल और सत्ता परिवर्तन की मंशा से जुड़ी खबरों ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि क्या यह सब लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या फिर संसाधनों पर नियंत्रण की वही पुरानी कहानी, जो इराक से लेकर पनामा तक दोहराई जाती रही है।

अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कथित बयान कि वेनेजुएला का तेल अब अमरीका की भागीदारी से चलेगा। केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि दशकों पुरानी रणनीति की गूंज है। वेनेजुएला का तेल साधारण नहीं है। यह भारी, गाढ़ा क्रूड है जिसे रिफाइन करने की क्षमता अमरीका की बड़ी रिफाइनरियों के पास है। कभी एक समय था जब अमरीका प्रतिदिन लाखों बैरल तेल वेनेजुएला से आयात करता था। बाद में प्रतिबंधों, राजनीतिक टकराव और आंतरिक संकट के चलते यह सिलसिला टूट गया। आज वही तेल, वही जरूरत और वही भूख एक बार फिर वैश्विक राजनीति को दिशा दे रही है।

मादुरो को लेकर अमरीका का आरोप रहा है कि उनका शासन तानाशाही, भ्रष्ट और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसमें संदेह नहीं कि वेनेजुएला के भीतर आर्थिक संकट गहरा है, जनता महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी वस्तुओं की कमी से जूझ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी देश के आंतरिक संकट का समाधान बाहरी सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप है। क्या लोकतंत्र की स्थापना बमों, गिरफ्तारियों और तेल समझौतों के जरिए की जा सकती है। इतिहास इस सवाल का जवाब देता है, लेकिन वह जवाब अमरीका के पक्ष में कम ही जाता है। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के पीछे भी हथियारों और लोकतंत्र की दुहाई दी गई थी। नतीजा क्या हुआ, यह दुनिया ने देखा। लीबिया में गद्दाफी के पतन के बाद स्थिरता आई या अराजकता, यह भी किसी से छिपा नहीं। पनामा में मैनुअल नौरिएगा की गिरफ्तारी, हैती और आइवरी कोस्ट में सत्ता परिवर्तन, चेकोस्लोवाकिया में बाहरी दबाव हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। पहले नैतिकता की भाषा, फिर रणनीतिक हित और अंत में संसाधनों पर नियंत्रण।

वेनेजुएला के मामले में यह पैटर्न और भी साफ दिखता है। एक ओर रूस, चीन और ईरान जैसे देश खुलकर अमरीकी हस्तक्षेप की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वेनेजुएला को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है। दूसरी ओर अमरीका इसे लोकतंत्र की बहाली के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन जब किसी हमले के तुरंत बाद तेल उद्योग में बड़े पैमाने पर अमरीकी भागीदारी की घोषणा होती है, तो संदेह स्वाभाविक है।

डॉनल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति इसी संदेह को और गहरा करती है। यह नीति मूल रूप से अमरीकी हितों को सर्वोपरि रखने की बात करती है, चाहे इसके लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों, संप्रभुता और कूटनीतिक मर्यादाओं को क्यों न ताक पर रखना पड़े। सवाल यह नहीं है कि कोई देश अपने हितों की रक्षा करे या नहीं, सवाल यह है कि क्या किसी दूसरे देश की कीमत पर ऐसा करना जायज है।

मादुरो को पकड़ना सही था या गलत, इसका उत्तर एकतरफा नहीं हो सकता। यदि मादुरो ने अपने देश के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, तो इसका निर्णय वेनेजुएला की जनता और वहां की न्यायिक व्यवस्था को करना चाहिए। बाहरी ताकतों द्वारा किसी राष्ट्रपति को हटाना या पकड़ना अंतरराष्ट्रीय कानून की आत्मा के खिलाफ जाता है। यह न केवल उस देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाता है, बल्कि भविष्य में और अधिक अस्थिरता को जन्म देता है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि वेनेजुएला की सड़कों पर मादुरो के समर्थन में उतरे लोग सिर्फ किसी नेता के समर्थक नहीं हैं, बल्कि वे उस डर की अभिव्यक्ति हैं कि कहीं उनका देश एक बार फिर किसी वैश्विक शक्ति के प्रयोगशाला में न बदल जाए। लैटिन अमरीका का इतिहास ऐसे प्रयोगों से भरा पड़ा है, जहां बाहरी हस्तक्षेप ने दशकों तक घाव दिए हैं।

अमरीका के भीतर भी इस तरह की कार्रवाइयों पर सवाल उठते रहे हैं। क्या सचमुच लोकतंत्र बंदूक की नली से निर्यात किया जा सकता है। क्या किसी देश की जनता की तकलीफों का समाधान उसके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण से होगा। वेनेजुएला का संकट जटिल है। यह सिर्फ मादुरो बनाम विपक्ष का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक प्रतिबंधों, तेल कीमतों, आंतरिक नीतियों और अंतरराष्ट्रीय दबावों का मिश्रण है। इसे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से हल करना सरलीकरण होगा। ट्रंप सही थे या गलत, यह सवाल भी इसी जटिलता से जुड़ा है। उनके समर्थक कहेंगे कि अमरीका ने अपने रणनीतिक और ऊर्जा हितों की रक्षा की। आलोचक कहेंगे कि यह साम्राज्यवादी सोच का नया संस्करण है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। लेकिन इतना तय है कि जिस क्षण लोकतंत्र की भाषा तेल के सौदों से जुड़ जाती है, उस क्षण नैतिकता कमजोर पड़ने लगती है।

दुनिया आज बहुध्रुवीय हो रही है। रूस, चीन और अन्य ताकतें अब हर मामले में अमरीका की अगुवाई स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वेनेजुएला का मुद्दा इसी बदलती वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक है। यह सिर्फ एक देश या एक राष्ट्रपति की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष की कहानी है, जिसमें संसाधन, सत्ता और सिद्धांत आमने-सामने खड़े हैं।

अंततः सवाल यह होना चाहिए कि वेनेजुएला की जनता क्या चाहती है। शांति, स्थिरता और सम्मानजनक जीवन। यह लक्ष्य बाहरी दखल से नहीं, बल्कि संवाद, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आंतरिक सुधारों से हासिल हो सकता है। यदि अमरीका सचमुच लोकतंत्र और मानवाधिकारों के पक्ष में है, तो उसे तेल से पहले इंसान को प्राथमिकता देनी होगी। वरना इतिहास एक बार फिर यही लिखेगा कि सत्ता के खेल में आदर्श हार गए और तेल जीत गया।

कांतिलाल मांडोत

बेटियों की ओर झुकती दुनिया बदलती सोच टूटती सदियां पुरानी परंपराएं

सदियों तक जिस दुनिया ने वंश चलाने के नाम पर बेटों को प्राथमिकता दी, उसी दुनिया में आज एक गहरा और सुखद बदलाव आकार ले रहा है। भारत, चीन जैसे विकासशील देशों से लेकर अमेरिका और यूरोप तक, समाज की सामूहिक चेतना में बेटियों को लेकर दृष्टिकोण बदल रहा है। जो बेटी कभी बोझ मानी जाती थी, वही आज भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवार की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखी जाने लगी है। यह बदलाव केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि सोच, संवेदना और रिश्तों के पुनर्परिभाषित होने का संकेत है।

भारत में यह परिवर्तन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 1999 में जहां 33 प्रतिशत परिवार बेटों की चाहत रखते थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर करीब 15 प्रतिशत रह गया है। शहरी भारत में एक बच्चा और वह भी बेटी,यह सोच तेजी से स्वीकार की जा रही है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि सामाजिक आंदोलनों, शिक्षा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सरकारी अभियानों का संयुक्त परिणाम है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी मुहिम ने केवल नारे नहीं दिए, बल्कि समाज के मानस में लंबे समय से जमी धारणाओं को चुनौती दी।

चीन का उदाहरण भी इसी दिशा में संकेत करता है। वहां 2000 में जन्म के समय लिंगानुपात 117 तक पहुंच गया था, जो दुनिया में सबसे असंतुलित स्तरों में से एक था। लेकिन 2023 तक यह घटकर करीब 111 हो गया। भारत में भी 2010 में 109 रहने वाला यह अनुपात अब 107 तक आ चुका है। यह पूरी तरह संतुलित भले न हो, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि समाज धीरे-धीरे प्राकृतिक औसत की ओर लौट रहा है। यह उस दौर के बाद का बदलाव है, जब अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों के दुरुपयोग ने जनसांख्यिकीय संतुलन को बुरी तरह बिगाड़ दिया था और करोड़ों बेटियों को जन्म लेने से पहले ही दुनिया से वंचित कर दिया गया।

पिछले पच्चीस वर्षों में भारत में करीब 70 लाख बेटियों का बचाया जाना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक परिवर्तन का प्रमाण है, जिसमें बेटी को जीवन का भार नहीं, बल्कि जीवन का आधार माना जाने लगा है। यह बदलाव केवल भारत या एशिया तक सीमित नहीं है। यूरोप, स्कैंडिनेवियाई देशों और जापान जैसे विकसित समाजों में भी माता-पिता अब बेटियों को प्राथमिकता देने लगे हैं। जापान में एक बच्चा चाहने वाले करीब तीन-चौथाई दंपती बेटी को प्राथमिकता देते हैं। स्कैंडिनेविया में दो बेटियों वाले परिवारों की संख्या अब दो बेटों वाले परिवारों से अधिक हो रही है। यह दर्शाता है कि आधुनिक समाज रिश्तों को केवल उत्तराधिकार या नाम के विस्तार से नहीं, बल्कि भावनात्मक संतुलन और जीवन की गुणवत्ता से जोड़कर देखने लगा है।

इस बदलती सोच के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण भावनात्मक जुड़ाव है। सामाजिक शोध और पारिवारिक अनुभव बताते हैं कि बेटियां माता-पिता के साथ अधिक संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और स्थायी भावनात्मक संबंध बनाती हैं। उम्र बढ़ने के साथ जब माता-पिता को देखभाल, संवाद और साथ की जरूरत होती है, तब बेटियां अधिक निकट और सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में, जहां संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और अकेलापन बढ़ रहा है, वहां यह भावनात्मक सुरक्षा एक बड़ा कारण बनकर उभरी है।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण आर्थिक और सामाजिक बदलाव है। महिलाएं अब केवल घरेलू दायरे तक सीमित नहीं हैं। शिक्षा, रोजगार, राजनीति, खेल, विज्ञान और अंतरिक्ष तक में बेटियों ने अपनी क्षमता साबित की है। वे न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि परिवार के आर्थिक फैसलों में भी बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। जब बेटी कमाने लगती है, फैसले लेने लगती है और माता-पिता के लिए संबल बनती है, तो उसे बोझ मानने की मानसिकता स्वतः कमजोर पड़ जाती है। दहेज जैसी कुरीतियों में आई कमी और कानूनी सख्ती ने भी इस सोच को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।

इस पूरे बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उभरता है।जब बेटियों की चाहत बढ़ रही है, तो बेटों से दूरी क्यों महसूस की जाने लगी है। इसका उत्तर बेटों के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना में आए बदलाव में छिपा है। पारंपरिक समाज में बेटों से यह अपेक्षा जुड़ी होती थी कि वे माता-पिता के साथ रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और परिवार का नाम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आधुनिक शहरी जीवन में बेटों पर करियर, स्थानांतरण और आर्थिक दबाव इतने बढ़ गए हैं कि वे अक्सर माता-पिता से भौतिक रूप से दूर हो जाते हैं। नौकरी के अवसर उन्हें दूसरे शहरों या देशों तक ले जाते हैं, जहां परिवार से दूरी एक मजबूरी बन जाती है।

इसके विपरीत, बेटियां अब भी भावनात्मक रूप से जुड़े रहने की कोशिश करती हैं, चाहे वे शादी के बाद किसी और शहर में क्यों न हों। तकनीक, संवाद और बदलते पारिवारिक मानदंडों ने बेटियों को पराया धन की संकीर्ण परिभाषा से बाहर निकाल दिया है। वे मायके और ससुराल दोनों के बीच सेतु बन रही हैं। यही कारण है कि आधुनिक माता-पिता भविष्य की सुरक्षा और साथ के लिए बेटियों को अधिक भरोसेमंद मानने लगे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल होते जेंडर रिवील वीडियो और जेंडर डिसअपॉइंटमेंट पर खुली चर्चाएं भी इस बदलाव की ओर इशारा करती हैं। जहां पहले बेटे के जन्म पर जश्न और बेटी पर चुप्पी होती थी, वहीं अब कई परिवार बेटी के जन्म को गर्व और खुशी के साथ साझा कर रहे हैं। यह सार्वजनिक स्वीकृति निजी सोच को भी बदल रही है। गैलप इंटरनेशनल के 44 देशों में किए गए अध्ययन में 65 प्रतिशत लोगों का यह कहना कि बच्चे का जेंडर उनके लिए मायने नहीं रखता, इस वैश्विक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है।

भारत में इस बदलाव की आज की प्रासंगिकता और भी गहरी है। एक युवा देश होने के बावजूद भारत तेजी से बूढ़ी होती आबादी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि पारिवारिक संबंधों से भी तय होगी। बेटियां, जो भावनात्मक रूप से जुड़े रहकर माता-पिता की देखभाल करती हैं, इस सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ ही, लैंगिक संतुलन का सुधरना समाज में अपराध, असमानता और हिंसा जैसे मुद्दों पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है।

यह भी सच है कि जन्म के समय लिंगानुपात अभी पूरी तरह संतुलित नहीं हुआ है। ग्रामीण और कुछ सामाजिक वर्गों में पुरानी सोच अब भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह पिछले दो दशकों में अंतर तेजी से घटा है, वह उम्मीद जगाता है कि आने वाले वर्षों में यह संतुलन और सुधरेगा। मोदी सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पहल ने केवल सरकारी स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद के स्तर पर भी असर डाला है। इस मुहिम ने बेटी को बचाने से आगे बढ़कर उसे पढ़ाने, आगे बढ़ाने और गर्व का विषय बनाने की सोच को मजबूत किया है।

अंततः यह बदलाव केवल बेटियों की जीत नहीं, बल्कि पूरे समाज की जीत है। जब किसी समाज में जन्म से पहले ही किसी बच्चे का भविष्य तय न किया जाए, जब प्यार और अवसर लिंग से नहीं, क्षमता और संवेदना से तय हों, तभी वह समाज वास्तव में प्रगतिशील कहलाता है। बेटियों की ओर झुकती दुनिया इस बात का संकेत है कि मानवता धीरे-धीरे उस बिंदु पर लौट रही है, जहां जीवन का मूल्य उसकी पहचान से नहीं, उसके अस्तित्व से तय होता है। यह परिवर्तन भले ही अधूरा हो, लेकिन इसकी दिशा सही है और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।

कांतिलाल मांडोत

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, लैटिन अमेरिका में वामपंथियों के प्रभाव को नेस्त-नाबूद करने का प्रयास

अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला अमेरिकी साम्राज्यवाद का एक नया किंतु और अलोकतांत्रिक कदम है। इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ 195 देशों का मौन बहुत ही आश्चर्यजनक एवं चिंतनीय है। अमेरिकी दादागिरी अपने चरम पर पहुंच चुकी है अमेरिका ने वेनेजुएला लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए और विगत 12 वर्षों से लगातार शासन कर रहे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके आधिकारिक निवास से पत्नी सहित अगवा कर अमेरिका ले जाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर आरोप लगाकर उन पर आक्रमण किया तथा उनका अपहरण कर उन्हें अमेरिका शिफ्ट किया गया तानाशाही का आरोप तो डोनाल्ड ट्रंप लगाया जा रहा है किंतु यह कहावत सत्य है कि ÷समरथ को नहीं दोस् गोसाई÷ यानी समर्थ व्यक्ति का हर कार्य सही मान लिया जाता है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किया गया ताज़ा सैन्य आक्रमण केवल एक देश पर हमला नहीं बल्कि इक्कीसवीं सदी की ऊर्जा राजनीति, वामपंथ बनाम नव-साम्राज्यवाद, और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बीच टकराव का प्रतीक बनकर सामने आया है, जब अमेरिकी नेतृत्व ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है, यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब वेनेजुएला की वामपंथी सरकार ने अपने विशाल पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, सोने और प्राकृतिक गैस भंडारों पर राष्ट्रीय संप्रभुता को और सख्ती से लागू करते हुए अमेरिकी और पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रत्यक्ष उपयोग से बाहर रखने के निर्णय को दोहराया था, माना जा रहा है कि इसी निर्णय ने वॉशिंगटन में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी सत्ता-तंत्र ने इसे लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप का औचित्य बना लिया, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह हस्तक्षेप वस्तुतः ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व की पुनर्स्थापना की कोशिश है, इस हमले के बाद अर्जेंटीना की नई राजनीतिक दिशा ने खुलकर अमेरिका का समर्थन किया है और ब्यूनस आयर्स से जारी बयानों में इसे वेनेजुएला में ÷लोकतांत्रिक संक्रमण÷ की दिशा में आवश्यक कदम बताया गया, साथ ही यह कयास तेज़ हो गए हैं कि विपक्षी नेता कोरिना माचाडो को अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ सत्ता में स्थापित करने की कोशिशें तेज़ होंगी, हालांकि वेनेजुएला के भीतर इसे तख्तापलट की साज़िश बताया जा रहा है,

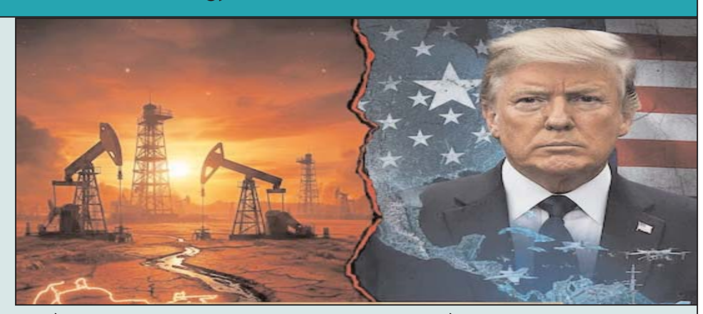

इस पूरे घटनाक्रम से चीन को बड़ा रणनीतिक झटका लगा है क्योंकि वेनेजुएला बीते वर्षों में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौतों और ऋण-तेल विनिमय व्यवस्था का अहम हिस्सा रहा है, अमेरिकी हस्तक्षेप से न केवल इन परियोजनाओं पर अनिश्चितता छा गई है बल्कि लैटिन अमेरिका में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की खुली कोशिश भी दिखाई दे रही है, इसी क्रम में रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने संयुक्त और अलग-अलग बयानों में इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है, रूस ने विशेष रूप से इसे संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप करार दिया और संकेत दिए कि अमेरिका की इस आक्रामक नीति ने वैश्विक अस्थिरता को और गहरा कर दिया है, उधर पूर्वी यूरोप में रूस-यूक्रेन संघर्ष ने भी नई तीव्रता पकड़ ली है और ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार रूसी सैन्य कार्रवाइयों में वृद्धि को कई विश्लेषक पश्चिमी दबाव और वेनेजुएला प्रकरण के व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं चीन के संदर्भ में ताइवान को लेकर बयानबाज़ी और सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी ने यह संकेत दिया है कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव का स्तर बढ़ रहा है, हालांकि बीजिंग ने आधिकारिक रूप से किसी तात्कालिक आक्रमण की घोषणा नहीं की है लेकिन यह स्पष्ट किया है कि ताइवान उसका आंतरिक विषय है और बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह वेनेजुएला पर हमला एक अकेली घटना न रहकर वैश्विक शक्ति संतुलन के पुनर्सयोजन का हिस्सा बनता जा रहा है, जहां अमेरिका अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों में निर्णायक बढ़त बनाए रखना चाहता है जबकि रूस और चीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करते हुए अमेरिकी एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं, लैटिन अमेरिका के कई देशों में इस घटनाक्रम को लेकर मतभेद उभर आए हैं, कुछ सरकारें अमेरिका के पक्ष में खड़ी दिखती हैं तो कई राष्ट्र इसे अपने लिए चेतावनी मानते हुए क्षेत्रीय संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप की नीति पर ज़ोर दे रहे हैं,

ऊर्जा बाज़ारों पर भी इसका असर दिखने लगा है जहां कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंता बढ़ी है, वेनेजुएला जो विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक का स्वामी है, लंबे समय से प्रतिबंधों और आंतरिक संकटों से जूझ रहा था, अब सैन्य हस्तक्षेप ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, मानवाधिकार संगठनों ने भी आशंका जताई है कि इस संघर्ष का सबसे बड़ा भार आम नागरिकों पर पड़ेगा, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसकी कार्रवाई का उद्देश्य लोकतंत्र और स्थिरता बहाल करना है, आलोचक इसे चयनात्मक नैतिकता बताते हैं क्योंकि समान परिस्थितियों में अन्य देशों के प्रति ऐसा रुख नहीं अपनाया गया, कुल मिलाकर वेनेजुएला संकट आज केवल कराकस या वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह मास्को, बीजिंग, ब्यूनस आयर्स, ताइपे और ब्रसेल्स तक फैली रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर रहा है और यह संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में विश्व राजनीति अधिक टकरावपूर्ण, संसाधन-केंद्रित और शक्ति-प्रदर्शन प्रधान होती जाएगी, जहां ऊर्जा, विचारधारा और सैन्य क्षमता तीनों मिलकर नए विश्व क्रम की दिशा तय करेंगे।

संजीव ठाकुर

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

सोमवार को होगा संपूर्ण समाधान दिवस, प्रशासन ने की व्यापक तैयारियां

लालगंज (रायबरेली)। तहसील परिसर में आगामी सोमवार को आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को अवकाश होने के कारण इस बार समाधान दिवस सोमवार को आयोजित किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। ग्रामीण व नगर क्षेत्र से बड़ी संख्या में फरियादियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए तहसील प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए परिसर में दो स्थानों पर अलाव जलवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पूरे तहसील परिसर की साफ-सफाई कराई गई है। समाधान दिवस में सभी विभागों के अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित की गई है, ताकि फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा सके। इस संबंध में एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले समाधान दिवस की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले किसी भी फरियादी को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

रेलकोच वाहन पार्किंग को लेकर ट्रक चालकों में मारपीट, तीन घायल

लालगंज (रायबरेली)। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के गेट नंबर तीन के पास शुक्रवार देर रात वाहन पार्किंग को लेकर दो ट्रक चालकों के बीच विवाद हो गया। बड़ुात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। बरेली जनपद के जरेल रोड, जरील नगर निवासी असमत ने बताया कि वह फरीदाबाद से रेलवे का सामान लेकर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना आया था। गेट नंबर तीन के पास ट्रक खड़ा कर वह खाना बना रहा था। इसी दौरान पंजाब के तरनतारन निवासी मनदीप सिंह वहां अपना ट्रक लेकर पहुंचे और जबरन ट्रक हटाने को कहने लगे। इसी बात को लेकर दोनों में गाली-गलौज शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मनदीप सिंह ने रिंच से असमत के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। बीच-बचाव करने पहुंचे परिचालक रहमत को भी पीटा गया, जिससे उसे भी चोटें आईं। वहीं, मारपीट में मनदीप सिंह के सिर पर भी चोट लगी है। घटना में दोनों पक्षों से कुल तीन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां असमत की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पीएम मोदी पर आपत्तिजनक मीम बनाना युवक को पड़ा महंगा, पुलिस ने लिया हिरासत में

लालगंज (रायबरेली)। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला कोतवाली क्षेत्र के उमरामऊ गांव का है। गांव निवासी यश कुमार पर आरोप है कि उसने एक सोशल मीडिया ऐप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो तस्वीरों का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक मीम बनाया और उसके साथ अमर्यादित टिप्पणी पोस्ट की। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने बताया कि उक्त पोस्ट से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट और वायरल पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पीआरवी पर पथराव मामला 5 आरोपी गिरफ्तार, दो पक्षों के विवाद में दो दिन पहले हुई थी घटना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर! जनपद सीतापुर के थाना अटरिया क्षेत्र में बीते शुक्रवार को पीआरवी वाहन पर पथराव कर शीशा तोड़ने की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अटरिया राकेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई को हैं टीम में ग्राम जानकीनगर निवासी दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार, अनूप कुमार, रामू सिंह पाल और सोनू उर्फ पुच्चू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 जनवरी 2026 की रात ग्राम जानकी नगर में दो पक्षों के बीच मारपीट और ईट-पत्थर चलने की सूचना पर डायल 112 की पीआरवी मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों द्वारा पीआरवी कर्मचारियों पर पथराव किया गया, जिससे वाहन के आगे और पीछे के शीशे टूट गए और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद सोनू उर्फ पुच्चू द्वारा फायरिंग भी की गई थी। इस संबंध में थाना अटरिया पर मुकदमा संख्या 003/2026 विभिन्न धाराओं में पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान नामित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त सोनू उर्फ पुच्चू के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 12 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। इस बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और इनके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। घटना में शामिल सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है!!

ज़मीन कब्जे का विरोध दबंगों ने पिता- पुत्र को मारी गोली, ग्राम प्रधान के भाई पर आरोप, बेटे की हालत गंभीर लखनऊ रेफर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर! जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के ग्राम अजीजपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि विवादित जमीन पर कब्जा करने के विरोध में हुए इस संघर्ष में दबंगों ने गोली चला दी, जिससे बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिता को भी छर्रे लगे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम अजीजपुर निवासी राजेश गुप्ता ने कुछ समय पहले पीड़ित पक्ष के भाई से जमीन खरीदी थी लेकिन राजेश बैनामा कराई गई जमीन से अधिक जमीन कब्जा करना चाहते है।

घटनाक्रम के अनुसार आज राजेश अपने करीब 50 लोगों और मजदूरों के साथ विवादित भूमि पर दीवार खड़ी कराने पहुंचे थे। आज जब पिता इंद्रपाल और उनके पुत्र शैलेन्द्र ने दीवार निर्माण का विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान दबंगों ने फायरिंग कर दी गोली लगने से शैलेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया वहीं पिता इंद्रपाल के हाथ और मुंह पर छर्रे लगने से वह भी घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया गया पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कब्जा करने वाला पक्ष प्रभावशाली है और उसमें ग्राम प्रधान का भाई भी शामिल है इसी राजनीतिक और सामाजिक दबदबे के बल पर वे जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहते थे पीड़ितों ने प्रशासन से जान-माल की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, क्षेत्राधिकारी मिश्रिख नेहा त्रिपाठी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा पुलिस ने गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों से घटना की जानकारी ली पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी!!

सभासद ने ठंड से राहत दिलाने के लिए जरूरतमंदों को वितरित किया कंबल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज/रायबरेली। बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए सामाजिक सरोकारों के तहत नगर पंचायत के आर्य नगर वार्ड में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ के सभासद जमुना पासवान ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए वार्ड की विधवा, बुजुर्ग और निराश्रित महिलाओं को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरित किए। आप को बता दें कि, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उन्होंने सभासद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि, जमुना पासवान ने अपने निजी खर्च से निराश्रित लोगों की मदद कर न केवल मानवता की मिसाल पेश की है, बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया है। उन्होंने आगे कहा कि जमुना पासवान अपने वार्ड की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। भारी संख्या में मौजूद रहे वार्डवासी कंबल पाकर बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे खिल उठे। इस वितरण कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से मोहित श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, स्वप्निल श्रीवास्तव, कमलेश अलीम सहित महिलाएं= सविता, राजवती, राजकुमारी, माधुरी, निर्मला, बिटाना, शिवकुमारी, राधा, कंचन, जुबैदा, अशिया, सबीना समेत सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं।

3197 सड़क हादसों में 139 लोगों ने गंवाई जान, 136 घायल

बलरामपुर। जिले में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ा है। वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 मेंन सिर्फ सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, बल्कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। जागरूकता कार्यक्रमों के बाद भी सड़क हादसों में कमी नहीं आई है। 2024 की अपेक्षा वर्ष 2025 में सड़क हादसों में 5.35, जबकि हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 12.10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं घायलों की संख्या भी 7.94 प्रतिशत बढ़ी है।वर्ष 2024 में जहां कुल 187 सड़क हादसे हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 197 पहुंच गई है। 2024 में हुए सड़क हादसों में जहां 124 लोगों ने जान गंवाई थी, वहीं वर्ष 2025 में 139 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही घायलों की संख्या भी 126 से बढ़कर 136 हो गई है। माहवार आंकड़ें पर नजर डालें तो जनवरी, फरवरी, मार्च व मई में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। जनवरी में मौतों की संख्या 85.71 प्रतिशत बढ़ी, जबकि फरवरी व मई में यह बढ़ोतरी 100 प्रतिशत तक पहुंच गई। मार्च में भी हादसों व मौत के आंकड़ें में बढ़ोतरी हुई है। एमएलके महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. राजीव रंजन का मानना है कि तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और जागरूकता की कमी हादसों की बड़ी वजह बन रही है। जिले में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन हादसे में किसी ने जान न गंवाई हो। वर्ष भर जिले में जागरूकता व चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी हादसों में कोई कमी नहीं आई है।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने कई लोगों के घर जाकर जाना कुशलक्षेम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन)= उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार रात क्षेत्रीय विधायक मूलचंद्र निरंजन के साथ कोंच में कई लोगों के आवास पहुंचे। उन्होंने राहुल तलवाड़ के आवास पर पहुंच कर उनके परिजनों से मुलाकात की। यहां भाजपा नेता विनोद अग्निहोत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह, प्रियेश पटेल, अमित लोहिया आदि ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जलशक्ति मंत्री भाजपा कोंच नगर अध्यक्ष अंजू रामबाबू अग्रवाल के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना। भाजपा अध्यक्ष ने जलशक्ति मंत्री को बतौर स्मृति चिन्ह भगवान राम का चित्र भेंट किया। जलशक्ति मंत्री ने यहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि एक-एक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। आगामी पंचायत चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरे मनोयोग से जुटने के लिए अभी से कमर कसनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताने की जरूरत बताई। इससे पहले मंत्री नया पटेल नगर स्थित साहिल पटेल के आवास पहुंचे और उनके परिजनों से भी मुलाकात की। वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल अग्रवाल की माताजी के निधन पर उनके आवास पहुंचकर मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की तथा

शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। इस दौरान विधायक मूलचंद्र निरंजन, बादाम सिंह कुशवाहा, धर्मेंद्र राठौर, विकास पटेल आदि मौजूद रहे।

उधार न देने पर दुकानदार से मारपीट, वीडियो सोशल पर वायरल

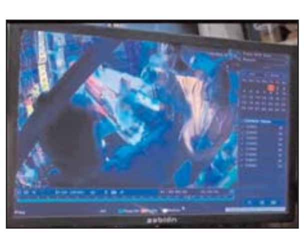

लालगंज (रायबरेली)। उधार सामान न देने पर दो लोगों ने एक दुकानदार के साथ मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली क्षेत्र के दोसड़का तिराहे का है। दोसड़का निवासी विमलेश चौरसिया की तिराहे पर पान और परचून की दुकान है। उन्होंने बताया कि दो लोग दुकान पर पहुंचे और उधार में सामान मांगने लगे। इनकार करने पर दोनों ने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट शुरू कर दी। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो एक जनवरी की रात का बताया जा रहा है। पीड़ित दुकानदार ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सैकड़ों चौकीदारो को बांटी गई किट, एएसपी बोले- ग्राम प्रहरी पुलिस की आंख- कान, रात्रि गस्त से रुकेगा क्राइम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर! जनपद सीतापुर के सभी ग्राम प्रहरी/चौकीदारों को प्रोत्साहित करने और उनके कार्यों को सम्मान देने के उद्देश्य से रिजर्व पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान एएसपी उत्तरी आलोक सिंह एवं सीओ सीई विनायक भोसले द्वारा सभी थानों के ग्राम प्रहरी एवं चौकीदारों की समस्याएं सुनी गईं और उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें किट के रूप में कंबल व टॉर्च वितरित की गई। कार्यक्रम में अधिकारियों ने ग्राम प्रहरियों से सीधे संवाद कर उनकी जिम्मेदारियों, चुनौतियों और स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने कहा कि ग्राम प्रहरी पुलिस प्रशासन की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं गांवों में घटित होने वाली छोटी-बड़ी घटनाओं की सूचना समय पर थाने तक पहुंचाकर वे अपराध नियंत्रण में सहयोग करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि ग्राम प्रहरी पुलिस की ÷आंख और कान÷ होते हैं।

उनकी सतर्कता और सक्रियता से कई बार बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी निष्ठा और जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाने वाले ग्राम प्रहरियों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, ताकि उनका मनोबल ऊंचा बना रहे और वे और अधिक समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। कार्यक्रम के दौरान ग्राम प्रहरियों को सम्मानित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास हैं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है और ÷कम्युनिटी पुलिसिंग÷ की अवधारणा को मजबूती मिलती है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ग्राम प्रहरियों को पुलिस परिवार का अभिन्न अंग माना जाता है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी मौजूद रहे कार्यक्रम के बाद ग्राम प्रहरियों में उत्साह और संतोष का माहौल देखने को मिला!!

धूमधाम से मनाया गया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ निर्मल खत्री का जन्मदिन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ निर्मल खत्री जी का जन्मदिन आज पूर्व विधायक हरीश बाजपेई के आवास पर धूमधाम से मनाया गया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरीश बाजपेई ने कहा की डॉक्टर निर्मल खत्री सन 1975 से अनवरत कांग्रेस की बेचारी को वैचारिकी को आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं एवं संरचनात्मक रूप से युवक कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस एवं राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठन के प्रमुख पदों पर रहे। अयोध्या से पूर्व सांसद रहे विधायक रहे तथा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जनप्रिय नेता हैं श्री वाजपेई ने उनके 75 में जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना की सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर उनके जन्म दिवस के अवसर पर केक काटा कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी विनीत दीक्षित शहर अध्यक्ष शिशिर बाजपेई, आमोद मिश्र कयूम अंसारी धीरेश कश्यप चोक्ष विभू अवस्थी संजय कुमार सनी, रिजवान खान, गिरीश दीक्षित,श्री प्रकाश राठौर,ओम प्रकाश मिश्रा जेपी शुक्ला संजय दीक्षित एम एल पांडे, राज गुप्ता श्याम जी शुक्ला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

एक भी जरूरतमंद को कंबल वितरण से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा- मूलचंद्र

● तीन गांवों में विधायक ने वितरित किए कंबल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

माधोगढ़ (जालौन)= कोंच-माधोगढ़ क्षेत्र के भाजपा विधायक मूलचंद्र निरंजन ने रविवार को विधानसभा क्षेत्र के माधोगढ़ एवं रामपुरा विकास खंड की अलग अलग ग्राम पंचायतों में ठंड से ठिठुर रहे गरीब वर्ग के जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। ग्राम झरैला, टीहर एवं धरमपुरा जागीर में आयोजित किए गए कार्यकमों में अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक ने जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित करते हुए कहा कि एक भी जरूरतमंद ग्रामीण को कंबल वितरण से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। इस दौरान विधायक ने उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और भाजपा की नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि सर्वसमाज के सभी वर्गों के कल्याण, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी निरंतर कार्य कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र को लेकर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों से लेकर विकास के अन्य सभी कार्यों को पूरा कराए जाने की लिए वह दृढ़ संकल्पित हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते विकास कार्य कराना उनका दायित्व ही नहीं, कर्तव्य भी है। इससे पूर्व प्रधान की अगुवाई में ग्रामीणों ने विधायक का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया।

इस मौके पर एसडीएम, नायब तहसीलदार सहित प्रधान भगवान सिंह प्रजापति, प्रदीप गौरव, अवनीश कुमार आदि मौजूद रहे।

-सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता का जनसैलाब

● महा हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नैनी, प्रयागराज। नैनी क्षेत्र में सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित महा हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। पार्षद राकेश जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों से आए धर्माचार्यों, विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। सम्मेलन का मुख्य केंद्र समाज में सद्भाव, युवाओं की भागीदारी और सांस्कृतिक एकता रहा। सांस्कृतिक प्रस्तुति और विचार प्रवाह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध गायक मिश्र बंधु एवं उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत सनातन गीतों से हुआ, जिसने पूरे पंडाल को राममय कर दिया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है।अतिथियों का स्वागत और प्रबोधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 श्री राम रतन दास जी महाराज (फलाहारी बाबा) एवं अध्यक्षता पूज्य संत चंद्रदेव मिश्रा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में सुबंधु (विभाग प्रचारक, प्रयागराज) ने युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथियों में प्रो. अलका (रज्जू भैया यूनिवर्सिटी), ज्ञानेश्वर तिवारी (गन्नू महाराज), पुष्पेंद्र सिंह (प्रकृति वेदा), और समर बहादुर सिंह शामिल रहे, जिनका आयोजक मंडल द्वारा माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय के प्रवक्ता श्री आशुतोष जी एवं हंडिया पीजी कॉलेज के डॉ. प्रद्युमन सिंह जी ने भी अपने विचार रखे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अभय प्रताप सिंह एवं मातृ शक्ति के रूप में मनोज दीदी की गरिमामयी उपस्थिति रही।विशाल जनसमूह की सहभागिता सम्मेलन में हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से घनश्याम जायसवाल, राजीव वर्मा, रजत दुबे, दिलीप केसरवानी, सचिन्द्र वैश्य, राम जी मिश्रा, सत्येंद्र जायसवाल (सत्या), सुरेश तिवारी, हरि कृष्ण तिवारी, राजेश शर्मा, राम बाबू केसरवानी, प्रेम प्रकाश जायसवाल, राजेश जायसवाल, राहुल जायसवाल, नरेन्द्र चौरसिया, राजन शुक्ला, सोनू मिश्रा, धर्मराज पटेल, विनोद जायसवाल, सुजीत जायसवाल, मुन्ना शर्मा, संजय केसरवानी, गनेशी सराफा, प्रमोद सिंह, बृजेश सिंह, श्यामधर मिश्रा, शशि शर्मा (लालु), संजय जायसवाल, और योगेश सिंह,जितेन्द्र सिंह, आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।आयोजक पार्षद राकेश जायसवाल ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष व्यक्त किया।

जनप्रतिनिधियों ने किया मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कदौरा(जालौन)= कस्बे के मेला मैदान में पं. दीनदयाल विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन रविवार को जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जादौन एवं नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना शिवहरे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। अतिथियों ने क्षेत्रवासियों से आपसी सौहार्द के साथ मेले का आनंद उठाने का आह्वान किया मेले का उद्घाटन करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा की मेले के आयोजन से एक ही स्थान पर जरूरत का सामान मिल जाता है। पूर्व विधायक ने कहा की मेले के आयोजन से भरपूर मनोरंजन होता है जिससे उनका तन मन स्वस्थ रहता है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा की नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पं. दीनदयाल विकास प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है जिसमे दूरदराज क्षेत्र से आने वाले दुकानदारों की समस्याओं को दूर कर मेले को भव्य व्यापक रूप दिया जाएगा। इस मौके पर चेयरमेन प्रतिनिधि

रविकांत शिवहरे, अनीस खान ठेकेदार, बब्लू शुक्ला, शिप्पू शुक्ला, राजवीर विश्वकर्मा, आफताब अहमद, शरीफ खान, बसीम राइन, आशीष शुक्ला, गंभीर गौतम, राहुल परिहार, रेनू वर्मा आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

मानवता की मिसाल- आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने किया रक्तदान

शहडोल- रक्तदान महादान% के संदेश को चरितार्थ करते हुए आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) शहडोल के जिला अध्यक्ष ने आज जिला अस्पताल/ब्लड बैंक पहुँचकर रक्तदान किया। उनकी इस पहल की जिले भर में सराहना की जा रही है।

जरूरतमंद की मदद के लिए बढ़ाया हाथ

जानकारी के अनुसार, जिला अध्यक्ष को एक गंभीर मरीज के लिए रक्त की आवश्यकता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही वे तुरंत अस्पताल पहुँचे और स्वयं रक्तदान कर मरीज की जान बचाने में अपना योगदान दिया।

युवाओं से की अपील

रक्तदान के पश्चात जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी के जीवन का आधार बन सकता है। उन्होंने जिले के युवाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे समय-समय पर रक्तदान करते रहें, ताकि किसी भी जरूरतमंद को रक्त के अभाव में परेशानी न झेलनी पड़े। "राजनीति केवल पद के लिएनहीं, बल्कि समाज की सेवा के लिए है। रक्तदान करना सबसे बड़ी मानवीय सेवा है।" - जिला अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी शहडोल

नगर पंचायत अध्यक्ष सुरियावा द्वारा किया गया क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन

सुरियावा 4 जनवरी 2026 को नगर पंचायत अध्यक्ष सुरियावा विनय चौरसिया द्वारा दुर्गागंज विकास क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय कंसरायबजहाडीह में क्रिकेट प्रतियोगिता मैच का फीता काटकर उद्घाटन किया तथा उद्घाटन मैच गोपीपुर बनाम पांडेपुर के बीच हुआ जिसमें पांडेपुर की टीम विजई हुई इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है खेल से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की युवा प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलता है हमारे क्षेत्र के तमाम ऐसे युवा प्रतिभावान खिलाड़ी आज देश प्रदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं इस मैच के आयोजक अंतिम तिवारी विपिन पांडे मौके पर पप्पू वर्मा विक्की सिंह बघेल गणेश जायसवाल पंजाबी मोदनवाल अंकित तिवारी अमित पांडे भूपेंद्र उपाध्याय तथा क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

NSCT 50,50 रुपये मात्र से 6 लाख का सहयोग किया

मीरजापुर। NSCT नेशनल सेल्फ केयर टीम हम सबका, हम सबके लिए, हम सबके द्वारा के भाव से (एनएससीटी) ने अपने पहला प्रयास में एक परिवार को छहः लाख रूपये से अधिक की आर्थिक मदद करके मानवता की अनोखी मिसाल पेश कीया है। मीरजापुर टीम ने पहला सहयोग गाजीपुर जनपद के एक दिवंगत सदस्य की पत्नी को किया है। इसमें टीम से जुड़े जिले मीरजापुर के 1500+ सदस्यों ने भी लगभग 75 हजार रूपये का योगदान किया है। NSCT के जिला मिडिया प्रभारी राहुल गुप्ता ने बताया कि सेवा परमो धर्म की भावना से प्रेरित होकर वर्ष 26 फरवरी 2025 को आम नागरिकों, कर्मचारियों अधिकारियों, संविदाकर्मियों, प्राइवेटकर्मियों आदि को आर्थिक, सामाजिक व विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए टीम का गठन किया गया। इसका उद्देश्य टीम से जुड़े सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु पर उसके आश्रितों को 50 लाख तक की आर्थिक सहायता, सदस्यों की बेटियों की शादी में सहयोग, गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मदद, जरूरतमंदों की शिक्षा में सहयोग, रक्तदान व स्वास्थ्य शिविरों समेत विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना है। NSCT टीम से अब तक प्रदेश के 30 हजार + लोग जुड़ चुके हैं टीम के सदस्यो ने गाजीपुर के अमेदा (सैदपुर) गांव निवासी आशुतोष गिरि को छहः अक्टूबर को निधन हो गया था। नियमानुसार उनकी पत्नी श्रीमती हेमा गिरि के बैंक अकाउंट में एक से 20 दिसम्बर तक मे मीरजापुर के हर सदस्यो ने 50-50 रुपये का सहयोग किया। इस छोटी सी धनराशी से उनके खाते में छः लाख से अधिक की रकम पहुंची है एनएससीटी के जिलाध्यक्ष इंजी. नरेंद्र यादव ने बताया कि अबतक मीरजापुर जिले के 2500 + लोग टीम के सदस्य बन चुके हैं। 1500+ सदस्यों ने स्व. आशुतोष गिरि के परिवार को 50-50 रुपये का सहयोग किया।

जिले के दुल्लभछड़ा बड़े बाज़ार में SMP के तहत कचरा और अपशिष्ट रखने के लिए घर निर्माण में लापरवाही

● विभागीय अधिकारी इंजीनियर मौन भूमिका में।

मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक का ध्यान आकर्षित।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि- वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास के माध्यम से विकास के लक्ष्य के लिए प्रत्येक जीपी की बिल्डिंग और MGNREGA के माध्यम से मिट्टी भरकर सड़क निर्माण के साथ हि साथ SMP के तहत कचरा और अपशिष्ट गृह निर्माण कार्य के लिए लाखों रुपये आवंटित कर रही है। लेकिन वह आवंटित सरकारी राशि जनता के विकास में उपयोग न करके भ्रष्टाचार के जरिए हड़पने की योजना के कारण आम नागरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिले के दुल्लभछड़ा खंड के विकास के अंतर्गत दुल्लभछड़ा जीपी के बड़ेबाजार में SMP के तहत ही कचरा और अपशिष्ट रखने के लिए घर निर्माण में महत्वपूर्ण लापरवाही की शिकायत जागरूक नागरिकों ने की। नागरिकों ने बताया कि SMP के तहत दुल्लभछड़ा जीपी में प्रत्येक वार्ड के कचरा और अपशिष्ट रखने के लिए स्थायी घर निर्माण कार्य शुरू किया गया लेकिन शुरुआत में ही भ्रष्टाचार चल रहा है और इस कार्य में जानकारी का कोई बोर्ड नहीं है। सरकार की दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए मनमाने तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। कार्य की स्थायित्व को लेकर जनता पहले से ही सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वह निर्माण कार्य बड़ेबाजार के सिंगला नदी के किनारे हो रहा है। इतनी निम्न गुणवत्ता का काम होने के कारण पहली बारिश में जलधारा से टूट जाने की संभावना है। यदि इस स्थान पर सही तरीके से काम नहीं किया गया तो जलधारा के कारण यह टूट जाएगा और सरकारी धन की बर्बादी होगी। निर्माण के लिए सरकारी तौर पर विभिन्न स्थानों पर लाखों रुपये का बजट आवंटित किया जा रहा है। लेकिन उस पैसे में भ्रष्टाचार के कारण और दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए काम जारी रखने के कारण जनता को वह सुविधा नहीं मिल रही। स्थानीय लोगों की तरफ से ठीक तरीके से निर्माण करने की चेतावनी देने के बावजूद इसे अनदेखा कर विभाग का इंजीनियर अपने मनमाने तरीके से काम चला रहा है। इस चुप्पी के कारण कार्य की स्थायित्व को लेकर जागरूक वर्ग में कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही भविष्य में दुर्घटना की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्पष्ट रूपरेखा के साथ कार्य किया जाए ताकि सरकार की छवि को नुकसान न पहुंचे और जांच के क्रम में उचित कार्रवाई के साथ-साथ सरकारी तौर पर आवंटित धन का सही तरीके से निर्माण कार्य की जानकारी बोर्ड लगाकर निर्माण कार्य किया जाए। सही तरीके से निर्माण कार्य हो, इस पर ध्यान देते हुए काम करने की मांग की जाती है। वहीं सूत्रों से पता चलता है कि SMP के अंतर्गत कचरा और अपशिष्ट गृह निर्माण कार्य की दिशा-निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थानों जैसे किसी भी मंदिर और शिक्षा संस्थान, विभिन्न प्रकार के ऑफिस समेत नदी के पास नियमों के अनुसार इन सभी स्थानों से काफी दूर विकल्पी स्थानों पर होना आवश्यक है। क्योंकि आसपास जमा होने वाले कचरे से तेज गंध फैल सकती है। लेकिन सरकार के दिशा-निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना यह कचरा गृह निर्माण कार्य बड़ेबाजार के मार्केट साइड की बिलकुल पास में किया जा रहा है। इस कार्य के सामने सिंघला नदी, शिक्षा संस्थान और मंदिर तथा लोगों के घनी आबादी वाले घर-बार हैं। इस संदर्भ में जागरूक नागरिकों ने सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार सही जांच के माध्यम से उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और विधायक विजय मालाकार का ध्यान आकर्षित किया। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।

अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी गिरोह पर दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 किलो हाई- ग्रेड चरस के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली को नशा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ड्रग-फ्री दिल्ली बाय 2026 अभियान के तहत दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस को एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस आयुक्त, दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए दक्षिण-पूर्वी जिला (स्श्वष्ठ) की स्पेशल स्टाफ टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक नशा तस्करी नेटवर्क पर करारा प्रहार करते हुए एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लगभग 10.970 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली चरस बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। यह बरामदगी न केवल दिल्ली बल्कि देश में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी 2026 को स्पेशल स्टाफ, दक्षिण-पूर्वी जिला को एएसआई अनिल के माध्यम से एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना अमर कॉलोनी क्षेत्र में एक ऐसा नशा तस्कर सक्रिय है, जो नेपाल से दिल्ली तक हाई-ग्रेड चरस की आपूर्ति में लगातार संलिप्त है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में निरीक्षक शुभम चौधरी, उप-निरीक्षक मुनेश, उप-निरीक्षक विनोद, उप-निरीक्षक राजवीर, उप-निरीक्षक राजेंद्र, एएसआई अनिल, हेड कांस्टेबल प्रेम, विवेक, दिनेश, पारवेश, महिला हेड कांस्टेबल संगीता तथा कांस्टेबल सतवीर, प्रदीप, छोटूराम और मोहित को शामिल किया गया। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व निरीक्षक राजेंद्र सिंह डागर, प्रभारी स्पेशल स्टाफ, दक्षिण-पूर्वी जिला द्वारा किया गया तथा एसीपी/ऑपरेशंस श्री हरि सिंह के निकट पर्यवेक्षण में यह ऑपरेशन संचालित किया गया।प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने थाना अमर कॉलोनी क्षेत्र में रणनीतिक रूप से जाल बिछाया। मुखबिर की निशानदेही पर शाम लगभग 6 बजकर 50 मिनट पर संदिग्ध व्यक्ति को चिन्हित किया गया और उसे रोका गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास मौजूद एक बैग से पॉलिथीन में पैक की गई भारी मात्रा में चरस बरामद हुई। जांच करने पर यह पाया गया कि बरामद मादक पदार्थ उच्च गुणवत्ता का है, जिसका कुल वजन 10.970 किलोग्राम है। इतनी बड़ी मात्रा में चरस की बरामदगी से यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी किसी छोटे स्तर पर नहीं, बल्कि एक संगठित अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के लिए काम कर रहा था।गिरफ्तार आरोपी की पहचान महेश पुत्र सुन प्रसाद, उम्र 46 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 02, रोलपा, थाना थवांग, जिला लिवांग, स्टेट राप्ती, नेपाल के रूप में हुई है। इस संबंध में थाना अमर कॉलोनी, दक्षिण-पूर्वी जिला, दिल्ली में एफआईआर संख्या 02/2026 दिनांक 2 जनवरी 2026 को धारा 21/61/85 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को विधि अनुसार गिरफ्तार कर आगे की

कानूनी कार्रवाई की जा रही है।पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से नेपाल से दिल्ली तक मादक पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति में संलिप्त था। उसने बताया कि कम समय में अधिक धन कमाने की लालच ने उसे इस अवैध धंधे की ओर धकेल दिया। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि हाई-ग्रेड चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक मांग और मुनाफे के कारण वह कानून के गंभीर परिणामों से अवगत होने के बावजूद इस अपराध में शामिल रहा। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और संपर्क सूत्रों की पहचान करने में जुटी हुई है, ताकि इस अंतरराष्ट्रीय नशा सिंडिकेट को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके।दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा और दिल्ली को नशा-मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त, जालौन मंडी में वाहन चालकों को दी गई अहम सलाह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई (जालौन)- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शुक्रवार को जालौन मंडी परिसर में बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में प्रवर्तन विभाग का स्टाफ और बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। अभियान का नेतृत्व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश कुमार द्वारा किया गया। अभियान के दौरान जिन वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं लगे पाए गए, उनमें मौके पर ही रिफ्लेक्टर लगाए गए। घने कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों को रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग कर सुरक्षित तरीके से वाहन संचालन की सलाह दी गई।

प्रवर्तन टीम द्वारा वाहन चालकों को यातायात सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। चालकों से अपील की गई कि वे सभी वैध प्रपत्रों के साथ ही वाहन चलाएं, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, ओवर स्पीड से बचें और गलत दिशा में वाहन संचालन न करें। इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट के वाहन न चलाने, कोहरे के समय वाहन की गति सीमित रखने तथा दृश्यता कम होने पर सुरक्षित स्थानों जैसे पेट्रोल पंप आदि पर वाहन खड़ा करने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के जागरूकता अभियानों का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना और आमजन को सुरक्षित परिवहन के प्रति सजग बनाना है। अभियान के अंत में सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य नियमों की भी जानकारी दी गई।

पूर्व प्रधान का नाम दो जिलों की मतदाता सूची में दर्ज, संशोधन की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- सुमेरपुर विकासखण्ड क्षेत्र के मवईजार गांव के पूर्व प्रधान का नाम बांदा और हमीरपुर–दोनों जिलों की मतदाता सूची में दर्ज पाए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पूर्व प्रधान महेश चंद्र शिवहरे ने बांदा एवं हमीरपुर के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को पत्र सौंपकर स्थिति स्पष्ट करते हुए आवश्यक संशोधन की मांग की है। पूर्व प्रधान महेश चंद्र शिवहरे ने अवगत कराया कि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उनका नाम बांदा शहर की मतदाता सूची में दर्ज हो गया था। हालांकि वे मूल रूप से हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मवईजार के निवासी और मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 से वे ग्राम पंचायत मवईजार की मतदाता सूची में शामिल हैं तथा वर्ष 2015 से 2020 तक ग्राम प्रधान पद का दायित्व भी निभा चुके हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में भरा गया एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) फॉर्म केवल उनके मूल पते ग्राम पंचायत मवईजार के आधार पर ही भरा गया है। ऐसे में बांदा शहर की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज रहना नियमों के अनुरूप नहीं है।

पूर्व प्रधान ने दोनों जनपदों के निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि बांदा की मतदाता सूची से उनका नाम हटाया जाए और मूल निवास ग्राम पंचायत मवईजार की मतदाता सूची में ही उनका नाम यथावत रखा जाए। उन्होंने कहा कि दो स्थानों पर नाम दर्ज होना अनजाने में हुई त्रुटि है, जिसे समय रहते ठीक किया जाना आवश्यक है। मामले को लेकर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।

मिर्जापुर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित बी डिविजन क्रिकेट टूर्नामेंट का

फाइनल उषा पेट्रोल पम्प ने आर.ओ. क्लब को आठ विकेट से हराकर जीता

मीरजापुर। शहर के लोहिया तालाब स्थित द्वारिका प्रसाद बजाज स्कूल के मैदान में मीरजापुर क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित "बी" क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच ऊषा पेट्रोल पंप व आर. ओ.क्लब के बीच खेला गया ,फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए आर. ओ. क्लब की पूरी टीम 16 ओवरों में मात्र 78 रन बनाकर आउट हो गई जिसमें शिवाय विष्वकर्मा 22 और सुजीत पाल ने 15 तथा जितेश ने 8 रनों का योगदान दिया जवाब में उषा पेट्रोल पम्प ने आठ ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर अपनी टीम को विजयी बना दिया।

आद्रे ने 45 रन मात्र 21 गेंदों पर बनाया तो वही वशिष्ठ ने 14 रन बनाकर अपनी टीम को पहली बार मिर्जापुर क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्राफी दिलवाया।मैन आफ द मैच का पुरस्कार आंद्रे को दिया गया।

फाइनल मैच के दौरान मौजूद रहे वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी दिनेश तिवारी, संतोष सिंह, राजीव सिंह , मंगल बॉस, विनोद यादव, प्रवीण कश्यप, शिव तिवारी, सुरेन्द्र यादव ,अनुराग यादव, आलोक यादव, टीटू यादव , पत्रकार अखिलेश मिश्रा देवेन्द्र पांडेय ,अभय मौर्या, रमेश दुबे, अंपायर राजकुमार यादव, अमर ज्योति, बृजेश यादव ,पंकज टण्डन ,सहित सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहे।

पट्टे की जमीन किसी की आवास योजना किसी का बकहो नगर परिषद में खेल

● जिला कलेक्टर से षिकायत कर कार्यवाही की गई मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बुढ़ार शहडोल- आवास योजना के लिए जहां भारत सरकार व प्रदेष सरकार समय समय पर समीक्षा बैठक व निचले स्तर पर निगरानी करने का प्रयास करती है, जिसके तरह गरीब लोगों को स्वयं पट्टे की जमीन या शासन की जमीन में आवास योजना देने का प्रयास रहता लेकिन बड़े आष्चर्य की बात है कि शहडोल जिले के बकहो नगर परिषद वार्ड क्र.5 अंतर्गत पट्टेदार कोई और आवास का मकान किसी और के नाम बन रहे क्या बकहो नगर परिषद के सी.एम.ओ. इंजीनियर आंख मूदकर व नियम कानून को दरकिनार करते हुए आवास का पैसा देकर जबरन पट्टेदार किसान की जमीन में अपात्र लोगों का आवास बनवाया जाना खुलेआम कानून का उल्लंघन है, जिसकी षिकायत वर्षो से पट्टेदार किसान अमित सिंघानिया द्वारा संभागीय कमिष्नर जिला कलेक्टर एवं जे.डी. नगरीय निकाय से षिकायत कर शीघ्र गलत ढ़ंग से नियम कानून से हटकर बन रहे आवास योजना के मकान को रद्द कर पट्टेदार को न्याय दिलाते हुए जमीन पर बन रहे आवास/ मकान को ध्वस्त कर जमीन खाली कराने की मांग की गई है।

पट्टेदार किसान अमित ने यह भी कहा कि जब मेरी जमीन वर्षो पुराने पट्टे से है, नगर परिषद बकहो में क्या कोई देखने सुनने वाला नही, की जहां मर्जी हो किसी की भी जमीन हो आवास योजना पास कर देते हैं, कही ऐसा तो नही की आवास योजना के पैसे में लेन देन कर दूसरे की जमीन में दूसरे के आवास को मंजूर कर बंदरबाट कर रहे हों, संभागीय कमिष्नर व कलेक्टर इस गम्भीर मुद्दे को लेकर लिखित षिकायत कर शीघ्र कार्यवाही की मांग की है।

उपयंत्रियां के बस्ते में दर्जनों ग्राम पंचायत का विकास कार्य हवा हवाई में

● संभागीय कमिष्नर व कलेक्टर से षिकायत कर कार्यवाही की मांग- तिवारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बुढ़ार शहडोल- म.प्र. सरकार निरंतर विकास की ओर प्रयासरत है, विकास को गति देने के लिए समय समय पर कमिष्नर व कलेक्टर जनपद सी.ई.ओ. या अन्य अधिकारियों को निर्देषित किए जाते हैं कि ग्राम पंचायत का विकास प्राथमिकता के तौर पर किया जाए लेकिन वर्षो से पदस्थ मठाधीष उपयंत्री जो बुढ़ार में पदस्थ है, उनके अधीनस्थ बोकरामार, कुड़ेली, खोहरा, नवाटोला, दर्षिला, रैकोबा, मोहतरा, चन्नौड़ी सेमरिहा छांटा चाका, ग्राम पंचायतों के विकास कार्य की फाइल उपयंत्री सचिव के जानकारी में है। न कि ग्राम पंचायत के विकास कार्य में तब्दील हुई है, इन ग्राम पंचायतों में पिछले दो वर्षो से कोई भी विकास कार्य नही दिख रहे है, ग्राम पंचायतों की जनता खुलेआम कह रही की क्षेत्र में उपयंत्री का नाम तक नही जानते सचिव क्या फाइल बनाकर किस तरह का विकास कार्य बंगलों के अन्दर कर वहीं सहायक यंत्री भी हॉ में हॉ मिलाकर भुगतान कर मालामाल हो रहे पर ग्राम पंचायत का विकास शून्य है। क्षेत्र का भ्रमण करने पर जनता दल यू किसान सभा के प्रदेष अध्यक्ष पूर्व भाजस अध्यक्ष विधायक दल नेता निजी सचिव बी.पी.तिवारी ने जब ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया देखा गया कि इन ग्राम पंचायतों में सड़क नाली डैम बांध सामुदायिक भवन आवास योजना से बन रहे मकान व जितनी भी म.प्र. शासन की योजना है, कोई भी कार्य नही दिख रहे।

प्रदेष नेता तिवारी ने यह भी कहा कि जनपद में पदस्थ सी.ई.ओ. क्या क्षेत्र में भ्रमण कर यह जानने का प्रयास किया की उपयंत्रियां द्वारा जो विकास कार्य की फाइले सी.ई.ओ. हस्ताक्षर के लिए जाती है, कभी आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, और अगर किया गया होता है, तो पंचायतों में हो रहे गड़बड़ी पर विराम जरूर लगता उक्त पंचायतां के उपयंत्री अपने घरों में बैठकर सभी फाइलों का मूल्यांकन कर भुगतान की प्रक्रिया कर रहे हैं संभागीय कमिष्नर व जिला कलेक्टर से संज्ञान में लेकर जिला स्तरीय सक्षम अधिकारी द्वारा पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण कर दोषी उपयंत्रियां के ऊपर कार्यवाही करते हुए शासन की योजनाओं के पैसें को बंदरबाट करने वाले दोषीजों पर कार्यवाही की मांग की गई है।

शिलचर NIT में आयोजित 3 असम बटालियन, NCC के वार्षिक प्रशिक्षण (CATC) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ दल (Best Contingent) पुरस्कार प्राप्त किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि शिलचर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की एनसीसी यूनिट ने एनआईटी शिलचर में आयोजित 3 असम बटालियन, एनसीसी के वार्षिक कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप (CATC) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ कंटिंजेंट (Best Contingent) पुरस्कार अपने नाम किया। इस प्रशिक्षण शिविर में विद्यालय के कुल 27 एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। कैंप का आयोजन दो चरणों में किया गया। पहला चरण 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक तथा दूसरा चरण 26 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चला। इस कैंप में 10 स्कूलों एवं कॉलेजों के एनसीसी कैडेटों ने सहभागिता की। कैंप के पहले चरण में कैडेट नादिम अब्बास बरभुइया ने सर्वश्रेष्ठ ड्रिल (DST) पुरस्कार प्राप्त किया, जबकि कैडेट देवाशीष दास ने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ ड्रिल (DST) पुरस्कार हासिल किया। वहीं, दूसरे चरण में शिलचर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के एनसीसी कैडेटों ने टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता में भी विजय प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती परवीन सुल्ताना लस्कर ने इस उल्लेखनीय सफलता के लिए सभी एनसीसी कैडेटों को हार्दिक बधाई दी। एनसीस सीटीओ साहिदुल इस्लाम चौधरी ने भी कैडेटों के अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कैंप के सफल संचालन में सक्रिय सहयोग के लिए प्रधानाचार्य का धन्यवाद किया और कैडेटों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ एनसीसी कैडेट सहनवाज़ लस्कर, मोहम्मद आदिल, मुस्तफा लस्कर और ताहिर हमीद के योगदान को भी कृतज्ञता के साथ याद किया। यह उपलब्धि न केवल विद्यालय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि एनसीसी कैडेटों की अनुशासनप्रियता, कठोर परिश्रम और मजबूत टीम भावना का भी सशक्त प्रमाण है।

स्व. सुदर्शन सिंह की पुण्यतिथि पर हुआ स्वास्थ्य मेले का आयोजन, 850 ग्रामीणों की हुई जांच

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई (जालौन)- बुंदेलखंड महापरिषद के संस्थापक स्वर्गीय सुदर्शन सिंह जादौन की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विकासखंड डकोर के ग्राम टिमरों में वृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन अनुरागिनी संस्था द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिवस पर संपन्न हुआ जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सदस्य नीरज गौतम रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी संघ के उपसभापति रामाशंकर जायसवाल उपस्थित रहे, माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन ने रहे। अतिथियों का स्वागत अनुरागिनी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र भेंट कर किया गया।

इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक एवं उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के निदेशक डॉ. प्रवीण सिंह जादौन ने कहा कि स्व. सुदर्शन सिंह जादौन ने अपना जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास

की रोशनी पहुंचाने के लिए समर्पित किया। अनुरागिनी संस्था विगत 28 वर्षो से महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्य अतिथि नीरज गौतम ने कहा कि स्वास्थ्य मेले जैसे आयोजन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं वंचित वर्गों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। विशिष्ट अतिथि रामाशंकर जायसवाल ने सहकारिता एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक मूलचंद्र निरंजन ने ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की अहमियत बताते हुए ऐसे आयोजनों की सराहना की। मुख्य

चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र भिटोरिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्वास्थ्य मेलों से समय रहते बीमारियों की पहचान संभव होती है। स्वास्थ्य मेले में कुल 850 ग्रामीणों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श सेवाओं का लाभ लिया। मेले में सामान्य रोग परीक्षण, रक्तचाप एवं मधुमेह जांच, महिला एवं बाल स्वास्थ्य परामर्श, आयुष एवं एलोपैथिक चिकित्सा सेवाएं तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने स्व. सुदर्शन सिंह जादौन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे।